क्लाइमेट चेंज एक गंभीर वैश्विक चुनौती : सीएम

मुख्यमंत्री ने मुंबई क्लाइमेट वीक-2026 में की सहभागिता

भोपाल, 19 फरवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि क्लाइमेट चेंज एक गंभीर वैश्विक चुनौती है और यह मानव अस्तित्व, आर्थिक स्थिरता और भावी पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा सवाल है.

डॉ. यादव मुंबई में क्लाइमेट वीक-2026 को संबोधित कर रहे थे. इस मौके पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला भी मौजूद थे. डॉ यादव ने कहा कि सतत् विकास की राह में हम पर्यावरण की अनदेखी नहीं कर सकते. विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना ही प्रगति का मूल आधार है. उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज के मामले में ठोस और समयबद्ध समाधान पर काम करना आज की जरूरत है. मध्यप्रदेश क्लाइमेट चेंज से निपटने में सर्वाधिक नवकरणीय ऊर्जा का उत्पादक बन लीडर की भूमिका में है.

मुख्यमंत्री ने नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इस राज्य में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों को हरसंभव सहयोग देने का विश्वास और सुरक्षा की गारंटी देते हुए कहा कि राज्य और निवेशक मिलकर देश को नवकरणीय ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे. बुधवार देर शाम के कार्यक्रम में मध्यप्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए राज्य के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग एवं ग्रीन एनर्जी के लिए विख्यात सिकोया क्लाइमेट फाउंडेशन के बीच मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में एमओयू हुआ.

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार मध्यप्रदेश में 300 मेगावाट 4 घंटे सौर-सह एनर्जी स्टोरेज परियोजना, 300 मेगावाट 6 घंटे सौर-सह एनर्जी परियोजना सहित 24×7 घंटे नवकरणीय ऊर्जा बैटरी आधारित एनर्जी स्टोरेज परियोजना पर काम कर रही है. यह एक नया प्रयोग है. यह भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना है. मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है. अपर मुख्य सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, मनु श्रीवास्तव ने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा, विद्युत आपूर्ति का एक कारगर, सस्ता और विश्वसनीय विकल्प है.

सीएम इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में होंगे शामिल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार 20 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026 में शामिल होंगे. समिट में वे उच्च-स्तरीय पैनल से चर्चा करेंगे. इसमें राज्य स्तर पर एआई के उपयोग से आर्थिक विकास को गति देने, डिजिटल सुशासन को सशक्त बनाने और मजबूत अवसंरचना विकसित करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव एआई कंप्यूटिंग, सायबर सुरक्षा संरचना, क्लाउड ईको सिस्टम, जनरेटिव एआई एकीकरण और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी प्रमुख वैश्विक तकनीकी कंपनियों के साथ वन टू वन बैठक भी करेंगे. बैठक में एडवांस्ड सेमीकंडक्टर ऐक्सीलरेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर और सॉवरेन एआई मॉडलिंग जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव टियर-2 शहरों से उभर रहे स्टार्ट-अप और नव प्रवर्तकों से भी मुलाकात कर उनके एआई आधारित कार्यों की जानकारी लेंगे.

मुंबई-इंदौर तेजस स्पेशल का संचालन बढ़ा 28 मार्च तक चलेगी ट्रेन

इंदौर. इंदौर से मुंबई के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहतभरी खबर है. यात्रियों की लगातार मांग और बेहतर प्रतिसाद को देखते हुए रेलवे ने मुंबई-इंदौर-मुंबई तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के संचालन की अवधि बढ़ा दी है. अब यह ट्रेन 28 मार्च तक संचालित होगी. रेलवे जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार गाड़ी संख्या 09085 मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस स्पेशल, जिसका संचालन पूर्व में 27 फरवरी तक निर्धारित था, अब 27 मार्च तक मुंबई सेंट्रल से रवाना होगी. इसी तरह गाड़ी संख्या 09086 इंदौर-मुंबई सेंट्रल तेजस स्पेशल, जिसका अंतिम फेरा 28 फरवरी तक तय था, अब 28 मार्च तक इंदौर से संचालित की जाएगी.

प्रदेश का मौसम बदला : कई जिलों में तेज बारिश

08 जिलों में बिजली-ओलावृष्टि का अलर्ट

भोपाल,19 फरवरी. फरवरी माह में मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदल गया है. राजधानी भोपाल में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना तो हुआ, लेकिन किसानों की चिंता भी बढ़ गई.

कई जिलों में ओलावृष्टि दर्ज की गई है, जिससे फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है. मौसम विभाग ने ग्वालियर-चंबल अंचल के आठ जिलों ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है.

प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन के प्रभाव से यह बदलाव देखने को मिल रहा है. दो अलग-अलग चक्रवाती परिसंचरण तंत्रों के सक्रिय होने से बादलों की आवाजाही बढ़ी है और कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है. कमोवेश मौसम गुरुवार को भी इसी तरह रहा.

बुधवार को भी रतलाम, श्योपुर, मुरैना, मंदसौर, नीमच और गुना सहित 20 से अधिक जिलों में कहीं तेज बारिश तो कहीं ओले गिरे. फरवरी में यह तीसरी बार है जब प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है. इससे पहले भी दो बार असामान्य मौसम ने किसानों की फसलों को प्रभावित किया था, जिसके बाद प्रशासन ने सर्वे कराए थे. 18 और 19 फरवरी को फिर से बदले मौसम ने खेतों में खड़ी फसलों को खतरे में डाल दिया है. हालांकि दिन के तापमान में वृद्धि देखी जा रही है और कई शहरों में पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, लेकिन रात और सुबह के समय ठंडक बरकरार है.

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के साथ है सरकार

भोपाल, 19 फरवरी. मध्यप्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों के प्रभावित होने की सूचनाओं के बीच किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है.

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है. हाल ही में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई वर्षा एवं ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के नुकसान की राहत राशि देने के लिए गंभीरता से कार्य किया जाएगा. कृषि मंत्री ने कहा कि जिन-जिन जिलों में वर्षा और ओलावृष्टि की घटनाएं सामने आई हैं, वहां तत्काल प्रभाव से प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण के आदेश दे दिए गए हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सर्वे कार्य पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि प्रभावित किसानों को राहत राशि का भुगतान समय पर किया जा सके

सिंहस्थ से पूर्व ब्लैक स्पॉट्स सुधारें, रिफ्लेक्टर और संकेतक लगाएं

- स्कूल वाहनों में सीसीटीवी और जीपीएस अनिवार्य
- हिट एंड रन मामलों में 32 लाख की राहत राशि स्वीकृत
- कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बैठक में चेताया

नवभारत न्यूज

उज्जैन. महाकुंभ 2028 से पहले जितनी तेजी से विकास कार्य निर्माण कार्य हो रहे हैं. ऐसे में सड़कों का रखरखाव भी जरूरी हो गया है. दुर्घटनाएं न हो इसके लिए रिफ्लेक्टर लगाए जाएं, ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाएं, उसमें सुधार किए जाएं और सीसीटीवी-जीपीएस भी दुरुस्त किए जाएं.

ये दिशा निर्देश उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह द्वारा गुरुवार को दिए गए. कलेक्टर रौशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय सभागृह में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सड़क सुरक्षा और शहर में चल रहे मार्ग चौड़ीकरण कार्यों की समीक्षा की गई. बैठक में कलेक्टर ने वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि यातायात नियमों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बैठक एवं निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कूमट, एडीएम अत्येन्द्र सिंह गुर्जर, एएसपी आलोक शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

सीसीटीवी और जीपीएस लगाएं- कलेक्टर ने स्कूल संचालकों को निर्देशित किया कि स्कूल वाहनों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाए जाएं तथा आरटीओ द्वारा फिटनेस का सत्यापन सुनिश्चित किया जाए. सड़क दुर्घटनाओं में घायल नागरिकों को गोल्डन अवर में त्वरित उपचार और समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सके, इसके लिए सभी विभागों को समन्वय बनाकर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए.

दुर्घटना में गिरावट- आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 की तुलना में 2026 में 1 जनवरी से 15 फरवरी तक सड़क दुर्घटनाओं के प्रकरणों की कमी आई है तथा घायलों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है. वर्ष 2025 में हेलमेट न लगाने पर 13,892 और सीट बेल्ट न लगाने पर 3,240 चालानी कार्रवाई की गई.

चौड़ीकरण का अवलोकन

कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने नगर निगम द्वारा किए जा रहे मार्ग चौड़ीकरण कार्यों का निरीक्षण किया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए. निरीक्षण के दौरान मंछामन मार्ग, कोयला फाटक से कंठाल चौराहा तथा खजूर वाली मस्जिद से केडी गेट चौराहे तक चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया गया. कलेक्टर ने संबंधित ठेकेदारों को तय समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने और निर्धारित मापदंडों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. नगर निगम के अधिकारियों को निर्माण स्थल पर उपस्थित रहकर कार्य की गति बढ़ाने तथा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रगतिरत कार्यों की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इसलिए जिम्मेदारी के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण किया जाए.

स्टेरिंग फेल होने से अनियंत्रित होकर पलटी बस, पांच घायल

नवभारत न्यूज

रीवा, 19 फरवरी, मऊगंज में गौतम ट्रेवल्स की बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 35 यात्री सवार थे. पांच यात्रियो को गंभीर चोटे पहुंची है जिन्हे उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गुरूवार की सुबह 10 बजे बस पतुलखी से रीवा की ओर आ रही थी तभी यह हादसा हुआ.

बस जैसे ही मुनमा मोड़ के पास पहुंची, अचानक स्टेरिंग फेल हो गई. जिससे चालक बस से नियंत्रण खो बैठा और बस सडक़ से नीचे उतर गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कन्डेक्टर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को रोकने की कोशिश की. वह बस से नीचे उतरकर टायर के नीचे पत्थर लगाकर बस को रोकने का प्रयास करता रहा, लेकिन बस रफ्तार और ढलान के कारण नहीं रुक सकी और करीब 5 फीट नीचे जा गिरी.

बस में लगभग 35 यात्री सवार थे, जिनमें स्कूली बच्चे और कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राएं भी शामिल थे, पांच लोग घायल हुए. वही हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. चीख-पुकार के बीच स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे. गांव के सरपंच रमेश कोरी और ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को बाहर निकाला और निजी वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया.

अभाविप ने सौंपे प्रांत अधिवेशन के प्रस्ताव

भोपाल,19 फरवरी. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) मध्यभारत प्रांत के प्रतिनिधिमंडल ने प्रांत मंत्री केतन चतुर्वेदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से शिष्टाचार भेंट की.

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अभाविप के 58वें प्रांत अधिवेशन में पारित प्रस्तावों की प्रति सौंपते हुए प्रमुख मांगों को सरकार के समक्ष रखा. अभाविप का 58वां प्रांत अधिवेशन 14 से 16 दिसंबर 2025 को डबरा में संपन्न हुआ था, जिसमें प्रदेशभर से आए प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए. पहले प्रस्ताव 'राज्य विश्वविद्यालय का उन्नयन - समय की मांग' में मध्य प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई.

इसमें अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय और भोज मुक्त विश्वविद्यालय के परिसरों के स्थानांतरण, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को तीन भागों में विभाजित करना, रिक्त पदों पर भर्ती सुनिश्चित करना और स्टार्टअप एवं इनोवेशन सेल को मजबूत करने जैसे सुझाव शामिल हैं. दूसरे प्रस्ताव 'राज्य विश्वविद्यालयों को एक संरचना में लाने की आवश्यकता' में मांग की गई कि विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों को 'उच्च शिक्षा विभाग' के एकल प्रबंधन के तहत लाया जाए.

दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान कार्यशाला संपन्न

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह एवं प्रशिक्षण के प्रभारी के .सी पटेल ने गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला को संबोधित किया. इस दौरान प्रदेश महामंत्री व सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी, प्रदेश मंत्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, संभाग प्रभारी विजय दुबे एवं अभय प्रताप सिंह यादव मंचासीन रहे.

6 लाख 50 हजार की बैटरियों के साथ 5 धराए

खरगोन. पुलिस ने भीलगांव में चल रहे प्लांट कंपनी के गोदाम से चोरी हुई साढ़े 6 लाख रुपए मूल्य की बैटरी चोरी मामले का पर्दाफाश करते हुए 2 सिक्योरिटी गार्ड और उनके 3 साथियों को गिरफ्तार किया है. जिसके जिम्मे सुरक्षा, निगरानी की जिम्मेदारी थी उसी सिक्युरिटी गार्ड ने कंपनी के गोदाम से चोरी का षडयंत्र रचकर वारदात को अंजाम दिया था. हालांकि सिक्योरिटी गार्ड की चतुराई पुलिस के सामने काम नही आई और चोरी में शामिल 4 साथियों के साथ सिक्युरिटी गार्ड भी पुलिस के शिकंजे में फंस गया है. हाल ही में थाना कसरावद में आत्मनिर्भर ऊर्जा प्रायवेट लिमिटेड भीलगांव के अधिकारी ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करायी थी.

अजय के सवालों पर घिरे मंत्री विजयवर्गीय

विधानसभा में ध्यानाकर्षण के दौरान बनी स्थिति

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 19 फरवरी. गुरुवार को एक ध्यानाकर्षण के दौरान सत्ता पक्ष के एक नहीं बल्कि दो विधायकों ने अपनी ही सरकार के मंत्री को जमकर कटघरे में खड़ा किया.

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा के वरिष्ठ सदस्य अजय विश्नोई के बीच विधानसभा में तल्खी साफ नजर आई.

अजय विश्नोई और नीरज सिंह ठाकुर ने जबलपुर जिले के नगरीय निकायों द्वारा घर-घर नर्मदा जल पहुंचाने की नवीन योजना के कार्यों में व्याप्त अव्यवस्थाओं का मामला ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया. उनका तर्क था कि 256 करोड़ रुपए की लागत से बनी जबलपुर जिले की भेड़ाघाट, पाटन, कटंगी, मझौली, पनागर और सिहोरा नगरीय निकायों में नर्मदा जल घर-घर पहुंचाने की योजना अब तक अधूरी पड़ी है. अब तक केवल आधे क्षेत्रों में ही नमदा का जल पहुंचा है, जिस कारण पुरानी योजना से काम चलाना पड़ रहा है. इस कारण पुरानी योजना के चलते बिजली और संचानल का खर्च निकायों पर 60 लाख से एक करोड़ तक बना हुआ है. अधिकारियों ने अधूरी योजनाओं का ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया है. इससे योजना के संचालन का भार निकायों पर आ गया है.

उन्होंने निकायों पर नई योजना का लाखों रुपए का बिजली का भार और स्वयं द्वारा नियुक्त 15-15 कर्मचारियों के वेतन का भार और कर्ज की वसूली का भार भी निकायों पर पड़ रहा है जो कि एक करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक है. इस बात पर मंत्री और विश्नोई में बहस की स्थिति बन गई.

इससे निकायों का विकास प्रभावित हो रहा है. इस पर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि योजनाएं पूरी हो गई है और उन्होंने बाकायता तिथि भी बता दिया कि योजनाएं कब पूरी हुई हैं. इस पर विश्नेई ने कहा कि क्षेत्र में पुरानी योजना के 184 में से 47 नलकुप बंद हुए हैं जो कि 25 फीसदी है. तीन चौथाई अब भी चालू हैं. हम अपने आपको धोखा दे रहे हैं, क्षेत्र के लोगों को भी धोखा दे रहे हैं. सीहोरा में 36 नए कर्मचारी रख लिए गए, जिन पर निकाय का कोई नियंत्रण नहीं है.

नारेबाजी | भाजपा सरकार पर वादों से मुकरने का आरोप लगाया

कांग्रेस ने विधानसभा परिसर में किया विरोध प्रदर्शन

भोपाल,19 फरवरी. मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र के चौथे दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में जोरदार और सांकेतिक प्रदर्शन किया.

इस दौरान विधायक हाथों में थाली लेकर सरकार के झूठे और खोखले वादों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जनता की शिकायतों को उजागर किया.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार केवल घोषणाओं और दावों तक सीमित है. उन्होंने कहा कि नौकरियों की घोषणाओं के बावजूद पिछले दो वर्षों में भर्तियां नहीं हो पाईं, जिससे बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ रही है. वहीं, लाड़ली बहनों को 3,000 रुपये प्रतिमाह का वादा केवल कागज पर रह गया है. बिजली बिलों में राहत, स्वास्थ्य व्यवस्था में पर्याप्त डॉक्टर और दवाइयां, किसानों को खाद और बीज सरकार ने इन सभी क्षेत्रों में केवल आश्वासन और 'ख्याली पुलाव' दिया है. सिंघार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण के मुद्दे और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को भी सरकार की खोखली नीति के उदाहरण के रूप में सामने रखा. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रदर्शन केवल राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि जनता की आवाज और उनके अधिकार, सम्मान और भविष्य की लड़ाई का प्रतीक है. कांग्रेस विधायक दल ने यह प्रदर्शन यह संदेश देने के लिए किया कि सरकार की घोषणाओं के पीछे वास्तविक कार्रवाई नहीं है. उमंग सिंघार ने कहा कि पार्टी जनता से जुड़े हर मुद्दे पर संघर्ष जारी रखेगी और विधानसभा से लेकर सड़क तक उनकी आवाज बुलंद करती रहेगी.

पेज एक का शेष

इंदौर के दूषित जल कांड को लेकर सदन में जबर्दस्त हंगामा

मंत्री ने कहा पहली मौत 21 से 29 दिसंबर के बीच हुई: चर्चा पर सत्ता पक्ष की आपत्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब सदन में श्वान के मामले में 47 मिनट की चर्चा हो सकती है तो फिर जिस मामले में लोग शांत हो गए हैं, उस मामले में चर्चा क्यों नहीं हो सकती. मैं ऐसे कई मामलों की सूची दे दूंगा, जब सब ज्यूडियश होते हुए भी मामले पर सदन में चर्चा हुई है. उन्होंने जानना चाहा कि मौत की शुरुआत कब से हुई और सहायता राशि कितनी दी गई? इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बाद में दो और लोगों की मौत हुई, जिससे मौतों की संख्या 22 तक पहुंच गई, वहीं मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है. पहली मौत 21 से 29 दिसंबर के बीच हुई.

हमने आईएएस अफसर को भी निलंबित किया : सीएम: इस पर नेता प्रतिपक्ष ने महज दो लाख रुपए की सहायता राशि को नाकाफी बताते हुए कहा कि घटना में 35 लोगों की मौत हो गई, क्या चार लाख रुपए रुपए देंगे. इस पर सीएम ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वैसे तो इस मामले में चर्चा सदन में नहीं कराया जाना था, लेकिन ऐसे विषय आने पर हमने मामले की गंभीरता को देखते हुए चर्चा कर समाधान का प्रयास किया है. इतनी बड़ी आबादी में नार्मल डेथ भी हो रही थी, हमने घटना के विषय में प्रशासनिक दृष्टि से आईएएस अफसर को भी निलंबित किया है. सवाल पैसे का नहीं संवेदनशीलता का है. दो की जगह चार क्या हम पांच लाख देने तैयार हैं.

क्या मंत्री, प्रभारी मंत्री, महापौर की जिम्मेदारी नहीं : सिंघार: वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि क्या जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की ही है? क्या इसके लिए मंत्री, प्रभारी मंत्री और महापौर जिम्मेदार नहीं है? नैतिकता के आधार पर मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया?

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60